RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 15 JANUARY TO 21 JANUARY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 21 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

तेल-गैस परियोजनाओं की नीलामी के पांचवें दौर में 11 ब्लाक रखे गए
Page 2

पाम ऑइल के बाद अब खिलौनों और टीवी के आयात पर लेगी रोक!
Page 4

सऊदी अरामको ने ग्रीन शू विकल्प का इस्तेमाल किया, IPO रेकॉर्ड 29.4 अरब डॉलर पर
Page 5

editoria!

सिर उठाती महंगाई

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी की वजह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में आए उछाल ने पहले से ही कमजोरी झेल रही अर्थव्यवस्था के लिए चिंता बढ़ा दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सीपीआई के जरिये जाहिर समग्र खुदरा महंगाई की दर दिसंबर में बढ़कर 7.35 फीसदी पर पहुंच गई, जो बीते छह वर्षों में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा है। खुदरा महंगाई के हिस्से के रूप में सबसे ज्यादा महंगाई खान-पान की चीजों में दर्ज की गई है, जो दिसंबर में बढ़कर 14.12 फीसदी हो गई है। नवंबर में यह 10.01 फीसदी दर्ज की गई थी। खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी कर कर सकती है। रिजर्व बैंक के हाथ बांधने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच मुख्य ब्याज दर में कटौती करके वास्तविक ब्याज दरों को ऋणात्मक दायरे में ले जाने का जोखिम कोई केंद्रीय बैंक नहीं उठाना चाहता। बहरहाल, मौजूदा हालात को लेकर अर्थ विशेषज्ञों की राय दो तरह की है। एक वर्ग का मानना है कि यह अस्थायी स्थिति है, जनवरी में मुद्रास्फीति तेजी से नीचे आ सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि करीब से देखने पर लगता है कि मुद्रास्फीति में उछाल अस्थायी प्रकृति का या किसी विशेष कारक की वजह से है। लेकिन कई अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल 'स्टैग्फ्लेशन' चरण में जा रही है। यह शब्द स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन से मिलकर बना है। जब विकास दर धीमी पड़ने लगती है, मांग में कमी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, और इसके समानांतर महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है तो इस अवस्था को स्टैग्फ्लेशन कहा जाता है। मौजूदा संकट को लेकर इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसके हालात पिछले कुछ वर्षों से बन रहे हैं। लोगों के खर्च में कमी आई है क्योंकि कई सेक्टरों में छंटनी हुई है और कुछ कारोबारी संस्थानों ने अपना निवेश घटा दिया है। मांग में गिरावट से कीमतें नीचे आनी चाहिए लेकिन तेल, दूध और सब्जियों की महंगाई इस तर्क को खारिज कर रही है। रिजर्व बैंक द्वारा पिछले साल पांच बार ब्याज दर में कटौती और वित्त बाजार में हजारों करोड़ रुपये के सरकारी प्रवाह का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि बैंक अपने कर्जे डूबने से दबाव में हैं। कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स कटौती का लाभ मिला है लेकिन वह निवेश के लिए आगे नहीं आ रहा। कारोबार में तेजी लाने के लिए ब्याज और घटाया जाए तो बाजार में पैसा बढ़ने से महंगाई और भड़क सकती है। इस तरह इकॉनमी एक कुचक्र में फंस सकती है जिसे तोड़ना मुश्किल होगा। वैसे ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि स्टैग्फ्लेशन जैसे बड़े नतीजे सिर्फ एक-दो महीनों के आंकड़े से नहीं निकाले जाने चाहिए।

बजट 2020 नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है सरकार

इस साल बजट (Budget 2020-21) में नौकरी करने वाले करदाताओं (Taxpayers) को मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) बजट में ऐसी स्कीम का ऐलान कर सकता है कि अगर आप छूट का मोह छोड़ देते हैं तो आपको लोअर फ्लैट रेट पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। इनकम टैक्स का यह स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स रेट पेश किया गया था, तब निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि जो कंपनियां किसी तरह के छूट का इंसेंटिव्स का फायदा नहीं लेती हैं उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 15 फीसदी तक रखा गया है। लाइव मिंट के मुताबिक, इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने के बाद सरकार अब इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को राहत देने की तैयारी में है। टैक्स स्लैब में किसी बड़े बदलाव के लिए तो अभी इंतजार करना होगा लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर जैसा ही इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए कोई स्कीम इस बार बजट में आ सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इनकम टैक्स का फ्लैट रेट 5 फीसदी से लेकर 30 फीसदी के बीच में रख सकती है। मुमकिन है कि यह रेट 15-18 फीसदी के बीच रह सकता है।

मौजूदा टैक्स स्लैब?

कर योग्य आय	टैक्स
2.5 लाख रुपए कोई	टैक्स नहीं
2.5 लाख से 5 लाख तक के	5 फीसद
5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक	20 फीसदी
10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर	30 फीसदी

साथ ही यह भी हो सकता है कि फ्लैट रेट सिर्फ 50 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आमदनी वाले टैक्सपेयर्स के लिए लागू हो। फिलहाल इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। इसके अलावा सेक्शन 80CCD (1B) के तहत NPS में निवेश करने पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देने पर भी 25,000 रुपए तक टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

तेल कंपनियों की माली हालत खराब

सरकार मांग रही 19000 करोड़ रुपये का डिविडेंड

नई दिल्ली। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ऑइल कंपनियों से रेकॉर्ड 19,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड मांग रही है। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि सरकार अपनी माली हालत ठीक करने के लिए इतनी रकम मांग रही है। ध्उ्ण और इंडियन ऑयल से कहा गया है कि वे इस कुल रकम में से करीब 60 प्रतिशत हिस्सा दें।

पिछले साल जितना नहीं हुआ प्रॉफिट

फाइनैंस मिनिस्ट्री ने मांग की है कि सरकारी ऑइल कंपनियों को इस साल डिविडेंड भुगतान या तो पिछली बार जितना रखना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी डिमांड करते समय यह भी तो देखा जाना चाहिए कि कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल जितनी नहीं है।

5 फीसदी ज्यादा डिविडेंड की मांग

अधिकारियों ने यह शिकायत भी रखी कि एक

ओर तो इन कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती जा रही है, दूसरी ओर वह ज्यादा डिविडेंड मांग रही है। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि ONGC को करीब 6,500 करोड़ रुपये, इंडियन ऑयल को 5,500 करोड़, BPCL को 2,500 करोड़, GAIL को 2,000 करोड़, ऑयल इंडिया को 1,500 करोड़ और इंजीनियर्स इंडिया को 1,000 करोड़ रुपये बतौर डिविडेंड सरकार को देने पड़ सकते हैं। इस साल जितने डिविडेंड की मांग की गई है, वह पिछले साल के मुकाबले करीब 5 प्रतिशत ज्यादा है।

विरोध कर रहीं कंपनियां

सूत्रों ने बताया कि कंपनियां इस मांग का विरोध कर रही हैं और यह रकम कम करने के लिए सरकार से बातचीत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इससे कम भुगतान की मांग मान ली जाए। अधिकारियों ने कहा कि इतना डिविडेंड देने के लिए कंपनियों को कर्ज भी लेना पड़ सकता है। एक एग्जिक्यूटिव ने कहा, 'जो मांग की जा रही है वह इस साल अब तक हासिल प्रॉफिट के अनुसार नहीं है।' इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में ध्ि को 4 प्रतिशत मुनाफा हुआ था। इसके अलावा बाकी सभी कंपनियों का मुनाफा घटा।

दुनिया के लिए पांच बड़े दीर्घकालिक संकट पर्यावरण से जुड़ेः डब्ल्यूईएफ

नई दिल्ली। दुनिया के सामने पांच सबसे बड़े दीर्घकालिक संकट पर्यावरण से जुड़े हैं। यह बात दावोस (स्विट्जरलैंड) के गैर सरकारी संगठन विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के सर्वे पर आधारित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में सामने आयी है।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2020 में तात्कालिक संकट आर्थिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बढ़ने का है।अंग्रेजी में ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट आफ दी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) में कहा गया है, ' एक ऐसे समय जबकि साझा संकटों से निपटने के लिए कंपनियों और सरकारों का मिलकर काम करना जरूरी है, हम ऐसी अस्थिर दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां भू राजनीतिक अशांति के चलते बड़ी शक्तियों के बीच मनमाने ढंग से प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही हैं।' यह रपट दस साल से आ रही है। पहली बार इसमें पहले पांच जोखिम पर्यावरण से जुड़े हैं। इन जोखिमों में अति कठोर मौसम की आपदा, मानव निर्मित पर्यावरणीय संकट, जैव विविधता की व्यापक क्षति, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन कम करने और उसके अनुकुल ढलने के काम में विफलता को रखा गया है। रपट में 2020 के अल्पकालिक जोखिमों में आर्थिक टकरावों, देशों के अंदर राजनीतिक ध्रुवीकरण, लू का प्रकोप, प्राकृतक संसाधनों और परिस्थितिकी का विनाश और साइबर हमलों की गिनती की गयी है।

तेल-गैस परियोजनाओं की नीलामी के पांचवें दौर में 11 ब्लाक रखे गए

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने बुधवार को तेल एवं गैस ब्लाक नीलामी के लिये पांचवें दौर की बोलियां आमंत्रित करने की घोषणा की। इस दौर में संशोधित वित्तीय शर्तों के साथ 11 ब्लाक नीलाम किए जा रहे हैं। खनिज तरल कार्बनिक ईंधन का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से हाइड्रोकार्बन खोज एवं लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत सरकार ढाई साल की छोटी अवधि में ही अबतक उत्खनन के लिए देश के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले 94 ब्लाक की पेशकश कर चुकी है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने एक बयान में कहा कि ये ब्लाक भारत के अधिकार क्षेत्र के 16 अवसादी बेसिनों में कुल 1,36,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं।

महानिदेशालय के अनुसार, ''खोज एवं उत्पादन गतिविधियों को आक्रमक तरीके से जारी रखने के तहत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के लिये पांचवें दौर की बोली शुरू की है...इसमें निवेशकों की बोली के लिये 19,800 वर्ग किलोमटर क्षेत्र में फैले 11 ब्लाक की पेशकश की जाएगी।'' पिछले दौर की बोली में सात ब्लाक के लिये केवल 8 बोलियां आयी थी। डीजीएच के अनुसार एचईएलपी व्यवस्था में चौथे दौर की बोली में खुला क्षेत्र

लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) जमीन पर स्थित सात ब्लाक की पेशकश की गयी थी। ये ब्लाक 18,510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले थे। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) सभी सात तेल एवं गैस ब्लाक लेने में सफल रही। ओएएलपी-4 संशोधित शर्तों पर पहले दौर की बोली थी। इसे फरवरी 2019 में मंजूरी मिली थी। जहां पिछली दौर की बोलियों में जहां ब्लाक उन कंपनियों को दिये जाते थे जो सरकार को तेल एवं गैस में अधिकतम हिस्सेदारी की पेशकश करती थीं वहीं छोटे और अबतक खोज से वंचित श्रेणी-दो और तीन बेसिन अब उन कंपनियों को दिये जा रहे हैं जो सर्वाधिक खोज एवं उत्पादन कार्यक्रम की पेशकश करती हैं।

डीजीएच ने कहा कि ओएएलपी-5 के लिये बोलियां 18 मार्च तक जमा करई जा सकती हैं। ओएएलपी के पांचवें दौर की बोली के कुल 11 ब्लाक 8 अवसादी बेसिन में फैले हैं। इसमें 8 जमीनी ब्लाक हैं। इसमें छह श्रेणी-1 बेसिन और एक-एक श्रेणी दो और श्रेणी तीन बेसिन में हैं। वहीं दो छिछले जल क्षेत्र (एक-एक श्रेणी-1 और श्रेणी-दो बेसिन) तथा एक गहरे जल क्षेत्र (श्रेणी 1 बेसिन) में स्थित है। डीजीएच के बयान के अनुसार, ''उम्मीद है कि ओएएलपी के पांच दौर के तहत खोज कार्य तुंरत शुरू होगा। इसमें 40 से 45 करोड़ डॉलर के निवेश का अनुमान है।'' बयान में कहा गया है, ''अबतक पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दौर की बोलियों में 1,36,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित ब्लाक आबंटित किये गये हैं। वहीं पांचवें दौर में 19,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ब्लाक की पेशकश की गयी है। इस प्रकार, इस दौर की बोली के बाद कुल खोज क्षेत्र बढ़कर 236,600 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।''

बजट में NBFCs को राहत संभव

दूर होगी कैश की किल्लत

नई दिल्ली। नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) की नकदी संकट को दूर करने के लिए बजट (Budget) में स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) या स्पेशल एंटिटि के गठन का ऐलान हो सकता है। सरकार की स्पेशल एंटिटी के जरिए NBFCs की फंडिंग की योजना है. नई एंटिटी का गठन पर्पज व्हीकल के तौर पर होगा।

स्पेशल एंटिटि में सरकार अपनी बची हुई एळळऊ की हिस्सेदारी डालेगी। इसके बाजार वैल्यू का करीब तीन गुना मार्केट से उधार लिया जा सकेगा. SUUTI की मौजूदा मार्केट वैल्यूएशन करीब 33,000 करोड़ रुपये है। ये करीब 1 लाख करोड़ रुपये बनेगा। इस SPV के जरिए जितने भी NBFCs इस समय कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं, उनकी मदद की जाएगी। मदद करने का तरीका भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तय करेगा. RBI तय करेगा कि किन NBFCs को इस एसपीवी के जरिए मदद देनी है। NBFCs में ये पैसा निवेश किया जाएगा जो उनकी बुक वैल्यू का 20 फीसदी तक हो सकता है। उससे NBFCs एक बार अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। NBFCs को मौजूदा पैसे की किल्लत से उबरने में मदद मिलेगी।

अंडर कंस्ट्रक्शन घर पर टैक्स छूट देने की तैयारी

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget) में घर खरीदारों को इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट में इससे जुड़े कई ऐलान हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार जारी है। सेक्शन 24 के तहत अभी ब्याज पर 2 लाख रुपये की छूट मिलती है। हाउसिंग मिनिस्ट्री इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना चाहती है. इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन मकान पर भी टैक्स छूट देने की तैयारी हो रही है।

वैश्विक संकेतों से कच्चे तेल का वायदा भाव फिसला

नयी दिल्ली। हाजिर बाजार की कमजोर मांग से कच्चे तेल का वायदा भाव बुधवार को 21 रुपये टूटकर 4,117 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चे तेल का जनवरी अनुबंध 21 रुपये या 0.51 प्रतिशत के नुकसान से 4,117 रुपये प्रति बैरल रह गया। इसमें 19,641 लॉट का कारोबार हुआ। इसी तरह कच्चे तेल का फरवरी अनुबंध 19 रुपये या 0.46 प्रतिशत के नुकसान से 4,134 रुपये प्रति बैरल रह गया। इसमें 1,292 लॉट का कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में ब्रेंट कच्चा तेल 0.26 प्रतिशत के नुकसान से 64.32 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

एनएचएआई ने एक दिन में 86 करोड़ रुपये का पथकर जुटाकर रिकॉर्ड बनाया

नयी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रविवार को 86.2 करोड़ रुपये पथकर संग्रह किया जो किसी एक दिन में अब तक का सबसे ऊंचा संग्रह है। एनएचएआई के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू ने यह जानकारी दी। पथकर वसूली की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली फास्टैग के जरिये जनवरी, 2020 में सबसे ऊंचा दैनिक संग्रह 50 करोड़ रुपये रहा है। इससे पहले नवंबर, 2019 में एक दिन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से 23 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था। संधू ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह के दौरान कहा, ''एनएचएआई का एक दिन का पथकर संग्रह रविवार को रिकॉर्ड 86.2 करोड़ रुपये रहा।'' उन्होंने कहा कि फास्टैग के जरिये किए जाने वाले दैनिक पथकर भुगतान की संख्या भी बढ़कर जनवरी, 2020 में औसतन 30 लाख प्रतिदिन हो गयी है। जुलाई में यह औसत आठ लाख था। दिसंबर, 2019 तक एक करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किये गए थे। उन्होंने बताया कि फास्टैग के क्रियान्वयन के मामले में जोधपुर टोल प्लाजा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। वहां 91 प्रतिशत पथकर संग्रह फास्टैग के जरिये हो रहा है। उन्होंने कहा कि फास्टैग के क्रियान्वयन में भोपाल और गांधीनगर टोल प्लाजा का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है।

कच्चा तेल की कीमतों को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं: प्रधान

कोलकाता। एजेंसी

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण कच्चा तेल की कीमतों में हुई वृद्धि से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यहां सीआईआई के एक कार्यक्रम से इतर कहा, ''सरकार ने प्रतीक्षा करो और नजर रखो का रुख अपनाया है। फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है।'' उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक कारणों से फारस की खाड़ी वाले इलाके में तनाव है। प्रधान ने कहा, ''वैश्विक बाजार में कच्चा तेल की कोई कमी नहीं है। हां, कच्चा तेल की कीमतों में कुछ तेजी आयी है, लेकिन पिछले दो दिनों में इसका दाम घटा भी है।''

पूर्वी क्षेत्र में 70 अरब डॉलर के निवेश की संभावनाएं देख रहा है इस्पात मंत्रालय

कोलकाता। एजेंसी

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि इस्पात मंत्रालय देश के पूर्वी क्षेत्र में इस्पात उद्योग से जुड़ी परियोजनाओं में कुल मिला कर 70 अरब डॉलर के निवेश की संभावनाएं देख रहा है। उनकी राय में ये परियोजनाएं क्षेत्र में विकास की गति तेज करेंगी। प्रधान यहां 'पूर्वोदय' कार्यक्रम के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के पिछड़े जिलों के विकास के लिये इन इलाकों में इस्पात उद्योग की परियोजनाओं का बड़ा योगदान हो सकता है।उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस कारण इस क्षेत्र में इस्पात उद्योग के विकास की बड़ी संभावना है। इस सूची में बिहार को भी शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय इस्पातनीति 2017 में 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता 30 करोड़ टन वार्षिक करने का लक्ष्य है। इसमें से 20 करोड़ टन पूर्वी क्षेत्र से आ सकता है। उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रधान ने कहा, ''आज भी देश में सालाना 14 करोड़ टन के इस्पात उत्पादन में नौ करोड़ टन पूर्वी क्षेत्र में हो रहा है।'' इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रसिका चौबे ने कहा कि पूर्वोदय कार्यक्रम में पूर्वी अंचल में बुनियादी ढांचे और माल लाने-ले जाने की सुविधा की कमी दूर करने की पहल भी होगी। उन्होंने कहा कि भारत को 2024-25 तक 5 हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में पूर्वोत्तर क्षेत्र ' बहुत सहज और संभावनापूर्ण स्थिति में है।''कोल इंडिया के चेयरमैन अनिल झा ने कहा, उनकी कंपनी प्रयासरत है कि देश में कोयले के आयात की आवश्यकता कम से कम रह जाए। कंपनी ने 2023-24 तक वर्षिक कोयला उत्पादन 90 करोड़ टन तक करने का लक्ष्य रखा है। अभी उत्पादन स्तर 60.7 करोड़ टन है। सरकारी इस्पात उपक्रम सेल के चेयरमैन ए.के. चौधरी ने कहा कि उनकी कंपनी के पूर्वी क्षेत्र में पांच कारखाने हैं। उनमें दो करोड़ टन उत्पादन हो रहा है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा कि तेल-गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से इस्पात की मांग और खपत बढ़ेगी।

आर्थिक सुस्ती की मार, इस साल कम होंगे 16 लाख जॉब्सः रिपोर्ट

मुंबई। आर्थिक सुस्ती के कारण रोजगार के नए अवसर बुरी तरह प्रभावित हुए है। चालू वित्त वर्ष (2019-20) में नई नौकरियों के अवसर एक साल पहले की तुलना में कम पैदा हुए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 में इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 16 लाख कम नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में कुल 89.7 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए थे।

कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की संख्या घटी है

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप के अनुसार असम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में नौकरी-मजदूरी के लिए बाहर गए व्यक्तियों की ओर से घर भेजे जाने वाले धन में कमी आई है। यह दर्शाता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की संख्या कम हुई है। इन राज्यों के लिए मजदूरी के लिए पंजाब , गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं और वहां से घर पैसा भेजते रहते हैं।

2018-19 में 89.7 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईइध) के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में 89.7 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए थे। चालू वित्त वर्ष में इसमें 15.8 लाख की कमी आने का अनुमान है। ईपीएफओ के आंकड़े में मुख्य रूप से कम वेतन वाली नौकरियां शामिल होती हैं जिनमें वेतन की अधिकत सीमा 15,000 रुपये मासिक है।

अप्रैल-अक्टूबर में ईइध से 43.1 लाख नए अंशधारक जुड़े

रिपोर्ट में की गई गणना के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर के दौरान शुद्ध रूप से ईपीएफओ के साथ 43.1 लाख नए अंशधारक जुड़े। सालाना आधार पर यह आंकड़ा 73.9 लाख बैठेगा। हालांकि इन ईपीएफओ में केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों और निजी काम-धंधे में लगे लोगों के आंकड़े शामिल नहीं है।

2004 में आंकड़े NPS को ट्रांसफर

2004 से ये आंकड़े राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत स्थानांतरित कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के एनपीएस की श्रेणी के आंकड़ों में भी राज्य और केंद्र सरकार में भी मौजूदा रुझानों के अनुसार 2018-19 की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 39,000 कम अवसर पैदा होने का अनुमान है।

बजट 2020

घट सकता है सोने पर आयात शुल्क, ज्वैलरी इंडस्ट्री कर रही है 4 फीसदी करने की मांग

नई दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य मंत्रालय ने आगामी बजट 2020-21 में सोने पर आयात शुल्क घटाने की मांग की है। जेम्स और ज्वैलरी को बनाने-तराशने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से ये सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय ने की है। सूत्रों के मुबाबिक वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को बजट के लिए सुझावों में सोने से आयात शुल्क घटाने पर विचार करने को कहा है। पिछले बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया था। इंडस्ट्री इसे घटाकर 4 फीसदी करने की मांग कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश का सोना आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में करीब सात प्रतिशत गिरकर 20.57 अरब डॉलर रह गया। वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 22.16 अरब डॉलर था। सोने के आयात में कमी से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली। 2019-20 के अप्रैल-नवंबर में व्यापार घाटा कम होकर 106.84 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी अवधि में व्यापार घाटा 133.74 अरब डॉलर पर था। भारत दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड आयातक देश है और ज्वैलरी इंडस्ट्री की मांग को पूरा करने कि लए इंपोर्ट किया जाता है। देश में सालाना 800-900 टन सोना आयात होता है। वहीं जेम्स और ज्वैलरी निर्यात अप्रैल-नवंबर अवधि में करीब 1.5 प्रतिशत गिरकर 20.5 अरब डॉलर रहा।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर बढ़ेगा दबावः फिच

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत में अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों को क्षेत्र में होने वाले नीतिगत बदलावों और रिलायंस रिटेल के ई-कॉमर्स कारोबार में कदम रखने से 2020 में दबाव का सामना करना पड़ सकता है। फिच सॉल्यूशंस ने जारी एक बयान में यह कहा है। उसका कहना है कि ई-कॉमर्स नीति पर काम चल रहा है और इसके मार्च से प्रभाव में आने की उम्मीद है। पहले जारी मसौदा दिशा-निर्देशों के तहत, विदेशी ऑनलाइन विक्रेताओं को उन कंपनियों या सहयोगियों के उत्पादों को बेचने से रोका गया है, जिनमें उनकी इक्विटी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, सरकार बड़े ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे उद्यमियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक नियामकीय प्राधिकरण स्थापित करने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है।

भारत ने चार देशों से तांबे की तारों के आयात पर सब्सिडी रोधी शुल्क लगाया

नयी दिल्ली। भारत ने चार देशों इंडोनिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से तांबे की तारों के आयात पर पांच साल के लिए सब्सिडी रोधी शुल्क लगा दिया है। सरकार की ओर से जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन देशों से तांबे की तारों के आयात से घरेलू कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि उसने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अंतिम निष्कर्षों पर विचार के बाद सब्सिडी रोधी या प्रतिपूर्ति शुल्क लगाने का फैसला किया है। डीजीटीआर ने इन चार देशों से तांबे की तारों के आयात पर सब्सिडी रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिपूर्ति शुल्क पांच साल के लिए होगा। बशर्ते इसे वापस नहीं लिया जाए या उससे पहले इसमें संशोधन नहीं किया जाए। डीजीटीआर ने अपनी जांच में पाया कि इन चारों देशों से इस उत्पाद का आयात सब्सिडी वाले मूल्य पर किया जा रहा है। पिछले साल घरेलू कंपनियों ने निदेशालय के समक्ष आवेदन दिया था कि इन चार देशों से तांबे की तारों को सब्सिडी वाली कीमत पर भारत भेजा जा रहा है।

अमेरिका ने कहा, चीन के साथ व्यापार करार से शुल्क नहीं घटेगा

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका और चीन बुधवार को पहले चरण के व्यापार करार पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि इस करार से चीन के अरबों डॉलर के सामान पर लगाए गए शुल्क वापस नहीं होंगे। अमेरिका के वित्त विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया, ''भविष्य में शुल्कों में कटौती की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बारे में अफवाहें पूरी तरह गलत हैं।'' 'ब्लूमबर्ग' की खबर में कहा गया है कि चीन के अरबों डॉलर के सामान पर शुल्क इस साल नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव तक जारी रहेंगे। उसके बाद इन्हें हटाया जा सकता है।

गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार, लाल निशान पर Sensex-Nifty, रुपया 14 पैसे टूटा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

मंगलवार को नए शिखर पर बंद घरेलू शेयर बाजार बुधवार सुबह मामूली गिरावट के साथ खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 22.85 अंक की गिरावट के बाद 41,929.78 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30.25 अंक की गिरावट के बाद 12,332.05 के स्तर पर खुला। बिकवाली की वजह से शुरुआती कारोबार में एक समय सेंसेक्स 110 अंक से अधिक लुढ़क कर 41 हजार 900 अंक के नीचे कारोबार करता दिखा। इसी तरह निफ्टी 40 अंक की गिरावट के साथ 12 हजार 320 अंक पर कारोबार कर रहा है।

अगर बाजार संभला तो सेंसेक्स 42 हजार के होगा पार

अगर ऐसा होता है तो सेंसेक्स 42 हजार के ऐतिहासिक स्तर को पार कर सकता है। मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। सेंसेक्स 92.94 अंकों की तेजी के साथ 41,952.63 पर और निफ्टी 32.75 अंकों की तेजी के साथ 12,362.30 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स ने 41,994.26 के रिकॉर्ड ऊपरी और 41,770.90 के निचले स्तर को छुआ।

इंडसइंड बैंक के शेयर में आई गिरावट

बीएसई इंडेक्स की बात करें तो शुरुआती कारोबार के दौरान निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक के शेयर में सबसे अधिक गिरावट रही। इंडसइंड बैंक की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं। इस तिमाही के दौरान बैंक का एनपीए बढ़कर 2.18 फीसदी पर पहुंच गया। इस वजह से बुधवार को बैंक के शेयर में 3 फीसदी की गिरावट आ गई।

शुरुआती कारोबार में रुपया 14 पैसे टूटा

अमेरिका-चीन के बीच पहले चरण के व्यापार करार से पहले निवेशकों के सतर्क रुख के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 14 पैसे टूटकर 71.01 प्रति डॉलर पर आ गया। फॉरेक्स डीलरों ने कहा है कि इस तरह की खबरों के बाद कि चीन के अरबों डॉलर के सामान पर शुल्क नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक जारी रहेंगा, के बाद रुपया और अन्य एशियाई मुद्राओं में गिरावट आई। अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया 14 पैसे के नुकसान के साथ 71.01 प्रति डॉलर पर चल रहा था। मंगलवार को रुपया 70.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

जब तक क्रूड $100 पार नहीं करेगा, तब तक मंदी नहीं आएगी: अर्थशास्त्री नौरिएल रुबिनी

एजेंसी

जानेमाने अर्थशास्त्री नौरिएल रुबिनी का कहना है कि अगर कोई यह सोच रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म हो गया है तो यह उसकी मासूमियत है। CFA सोसायटी इंडिया की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरव्यू में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 'डॉ डूम' के रूप में मशहूर रुबिनी ने कहा कि जब तक क्रूड $100 पार नहीं करेगा, तब तक मंदी नहीं आएगी।

■US ईरान में तनाव कम होने से बाजार ने संभावतः राहत की सांस ली है। क्या शांति बनी रह सकती है?

शांति अस्थायी है। ळए ईरान के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ने के आसार को बाजार हल्के में ले रहा है। बाजार कह रहा है कि दोनों के बीच जंग के आसार कम हैं, तो वह सही हो सकता है। अगर जंग होती है और ऑयल प्लांट्स को नुकसान पहुंचने पर क्रूड $100 प्रति बैरल पार हो जाता है और होरमुज़ स्ट्रेट ब्लॉक हो जाती है तो अमेरिका और दुनियाभर में मंदी आएगी। ट्रंप ऐसा नहीं चाहते लेकिन जंग नहीं होगी, ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि हालात कासिम सुलेमानी के मारे जाने से पहले जैसे हो जाएंगे। तनाव के बीच दोनों अलग-अलग तरह से लड़ेंगे। ईरान सीरिया, इराक, लेबनान या गाजा में तनाव पैदा कर सकता है। इस इलाके में या दुनियाभर में ळए, इजराइली ऐसेट्स या गल्फ ऐसेट्स पर पहले जैसे अटैक हो सकते हैं। क्रूड $70 तो पार कर सकता है लेकिन $100 के पार नहीं जाएगा। यह जंग होने पर ही होगा। $ 80 मेरे लिए बेसलाइन होगा। ईरान में नंबर दो की हैसियत रखने वाला शख्स मारा जा चुका है जो वहां का अगला प्रेसिडेंट बनने वाला था। क्या कोई इतना भोला हो सकता है कि ईरान 12 रॉकेट मारकर जीत का एलान कर देगा और कहेगा कि हमें अमेरिका के साथ जो करना था, कर दिया है?

■ग्लोबल इकॉनमी पर जंग का क्या असर होगा?

जंग के हालात बनने पर अगर ईरान होरमुज स्ट्रेट ब्लॉक करके टैंकरों पर हमले करता है या सऊदी अरब या UAE की ऑयल फसिलिटीज को बर्बाद कर देता है तो ऑयल के दाम $100 पार कर सकते हैं। उस स्थिति में समूची दुनिया मंदी का शिकार हो जाएगी लेकिन वह मेरी बेसलाइन नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कई मोर्चों पर सीधे या परोक्ष रूप से वर्चुअल और रियल फ्रंट पर बढ़ेगा। ऐसा होने पर क्रूड $80 की तरफ बढ़ सकता है। पिछले साल ळए-चीन ट्रेड वॉर या ब्रेग्जिट को लेकर बाजार में रिस्क लेने की कपैसिटी घटी थी, अब यह ळए-ईरान के बीच पैदा तनाव से हो रहा है। बिजनस सेंटीमेंट कमजोर होगा, पूंजी निवेश घटेगा, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में करेक्शन होगा और ऑयल $80 की तरफ बढ़ेगा। ग्रोथ पिछले साल से कम रह सकती है, व्यापक मंदी नहीं होगी जब तक कि जंग नहीं होती।

■दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों ने पिछले एक दशक से जो गैर-परंपरागत मॉनिटरी पॉलिसी अपनाई है, वह जारी रहेगी?

अगर फिर से मंदी आती है तो सभी देशों के सेंट्रल बैंक गैर-परंपरागत मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे। मैक्रोइकनॉमिक्स की सामान्य पाठ्यपुस्तक में QE या नेगेटिव पॉलिसी रेट का जिक्र नहीं होता। ये पॉलिसी परंपरागत रूप से प्रभावी टूल बन गई हैं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व स्पष्ट रूप से कह चुका है कि अगर मंदी आती है तो उसके पास सिर्फ 150 बेसिस पॉइंट की कटौती की गुंजाइश बचेगी। फेड यूरोप और जापान जैसा कदम उठाने के बारे में सोच रहा है। ECB और BOJ अब भी नेगेटिव जोन में है और ये अभी पब्लिक और प्राइवेट ऐसेट्स खरीद रहे हैं। फॉरवर्ड गाइडेंस देने के बाद QE लाते हुए फेड के पास कम से कम जीरो तक जाने की गुंजाइश है। अगर अगली मंदी बड़ी होती है, तो सेंट्रल बैंक QE पॉलिसी या फिस्कल डेफिसिट का पर्मानेंट मोनेटाइजेशन कर सकते हैं।

■इंडिया की ग्रोथ कमजोर हो रही है। राहत पैकेज पर चर्चा हो रही है। आपकी राय क्या है?

बात फिस्कल या मॉनिटरी पॉलिसी की नहीं है। RBI ने पिछले साल रेट पांच बार कट किए थे लेकिन उसका असर सिस्टम में नहीं दिखा क्योंकि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में दिक्कत है। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी सुधारों की जरूरत है। मुझे लगता है कि आपके प्रधानमंत्री ने आर्थिक मुद्दों से नजरें हटा ली हैं और ऐसे राजनीतिक कदम उठाने लगे हैं जिनसे उन्हें अल्पकालिक लाभ मिल सकता है लेकिन अगर इकॉनमी लुढ़की तो उनकी लोकप्रियता भी गिरेगी। उन्हें बहुत से काम करने की जरूरत है: क्रेडिट सिस्टम को दुरुस्त करना है, श्रम सुधार और भूमि सुधार करना है, इनोवेशन करना है, खेतीबाड़ी का हाल सुधारना है, कामगारों का वेतन बेहतर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को दुरुस्त करना है।

पाम ऑइल के बाद अब खिलौनों और टीवी के आयात पर लेगी रोक!

नई दिल्ली। एजेंसी

घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार खिलौनों और टीवी सेट्स जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के आयात में कमी कर सकती है। मलयेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑइल के आयात पर रोक लगाए जाने के बाद से कई अन्य सामानों के आयात को कम करने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। खबरें हैं कि इस बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी हैं। क्रूड पाम ऑइल पहले फ्री ट्रेड लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब उसे उस लिस्ट से बाहर कर रिस्ट्रिक्टेड आइटमों की लिस्ट में डाल दिया गया है। यानी अब पाम ऑइल के आयात के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत होगी।

पाम ऑइल के आयात पर रोक का कराण कश्मीर, सीएए पर मलयेशिया की टिप्पणियां थीं, लेकिन कुछ अधिकारियों ने समाचार एजेंसी को बताया कि पाम ऑइल आयात पर रोक लगाने के कारणों में घरेलू रिफाइनर्स को बढ़ावा देना भी एक प्रमुख कारण है, कम से कम शॉर्ट रन में। इसके अलावा, सरकार पाम ऑइल पर निर्भरता कम करने के उपायों पर भी काम कर रही है ताकि अन्य एडिबल ऑइल्स का उत्पादन व इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि खिलौनों के आयात पर रोक लगाने के लिए कई सुझाव मिले हैं। इसके लिए क्वॉलिटी कंट्रोल और अन्य स्तरों पर कई कदमों पर विचार किया जा रहा है। कुछ सिंगल ब्रैंड रूट एफडीआई के तहत आने वाले कुछ प्रमुख स्टोर्स के पास चीनी खिलौनों का बड़ा स्टॉक है और सरकार उन्हें प्रतिबंधित की श्रेणी में शिफ्ट करने के बारे में सोच रही है। कॉमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष के दौरान खिलौनों, गेम्स और स्पोर्ट्स के सामानों आदि का 4500 करोड़ रुपये का आयात किया गया था। इसमें से करीब 3200 करोड़ डॉलर का सामान चीन से आया था।

इसी तरह टीवी सेट्स जैसे वाइट गुड्स बनाने वाली घरेलू कंपनियां भी चीन और दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के सस्ते आयात पर निर्भर रहती हैं। सस्ते आयात पर लगाम लगाने के लिए हालांकि सरकार ने कोशिशें कीं लेकिन कई मामलों में यह कारगर साबित नहीं हुई। आयात पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाने का तरीका अपनाया, लेकिन कई ममालों में फायदा नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर, सैमसंग ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बजाय आयात का फैसला किया, ताकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत वह फायदा उठा सके।

आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए अर्थव्यवस्था में सरकारी पूंजी झोंकने की जरूरत: फिक्की

नयी दिल्ली। उद्योग मंडल फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने मंगलवार को सरकार से आग्रह किया कि वह राजकोषीय घाटे को लेकर चिंता न करे और नरमी को थामने तथा आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये सार्वजनिक पूंजी खर्च बढ़ाये। उन्होंने कहा, ''हमें अर्थव्यवस्था में पूंजी डालने की जरूरत है। सचाई यह है कि जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि में नरमी है और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये पर्याप्त पूंजी लगाने की जरूरत है। ऐसे में हमें राजकोषीय घाटे में हल्की वृद्धि को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए।'' रेड्डी ने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था में डेढ-दो लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे खपत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के पास पूंजी डालने को लेकर राजकोषीय गुंजाइश है, रेड्डी ने कहा कि सरकार के पास गुंजाइश है क्योंकि राजकोषीय घाटा अभी नियंत्रण में है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, ''एक उपाय यह है कि सरकार आरबीआई से पूंजी जुटाये।'' साथ ही सरकार को समयबद्ध तरीके से विनिवेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। फिक्की के नये अध्यक्ष ने निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, ''वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी केवल 1.7 प्रतिशत है और भारत जैसे देश के लिये यह काफी कम है। हमें इसमें वृद्धि लानी चाहिए।'' देश का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान करीब 2 प्रतिशत घटकर 212 अरब डॉलर रहा।

FICCI
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

केंद्र के स्टॉक में सड़ रहा है प्याज, क्योंकि... विदेशी प्याज को नही उठा रही राज्य सरकारें

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार के स्टॉक में आयातित प्याज सड़ रहा है और राज्यों ने प्याज लेने से मना कर दिया है। पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक 18,000 टन प्याज का आयात किया है, जिसमें से सिर्फ 2,000 टन राज्यों ने खरीदा है, बाकी प्याज पड़ा हुआ है।

पिछले कुछ दिनों से देश के बाजारों में प्याज की घरेलू आवक बढ़ने के कारण कीमतों में गिरावट आई है, जिसके बाद आयातित प्याज की मांग कमजोर पड़ गई। कारोबारियों ने बताया कि विदेशी प्याज का जायका देसी प्याज जैसा नहीं है, इसलिए उपभोक्ता विदेशी प्याज खरीदना नहीं चाहते हैं। मानसून के आखिरी दौर में देश में हुई भारी बारिश से प्याज की फसल खराब होने के कारण पिछले साल के आखिरी तीन महीनों में प्याज के दाम में बेहद इजाफा हो गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने करीब एक लाख टन प्याज का आयात करने का फैसला लिया ताकि उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को काबू किया जा सके। सरकार के आदेश पर विदेश व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी एमएमटीसी ने करीब 40,000 टन प्याज का आयात करने के सौदे किए, लेकिन विदेशों से प्याज आने पर कीमतों में नरमी आ गई है, जिसके कारण राज्यों ने आयातित प्याज खरीदने से हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय में सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी देते हुए बताया कि अब तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार से प्याज खरीदा है।

श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 18,000 टन प्याज विदेशों से आ चुका है और 4,000 टन अगले 16 जनवरी तक आएगा। इसके बाद 25 जनवरी तक 9,000 टन और 30 जनवरी तक 4,000-5,000 टन प्याज विदेश से आने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में प्याज का खुदरा दाम बीते महीने जहां 150 रुपये प्रति किलो तक चला गया था वहां यह अब 40-80 रुपये किलो बिक रहा है।

सस्ते इंपोर्ट से निपटने के लिए MSME को मिलेगी कानूनी मदद!

नई दिल्ली। सस्ते इंपोर्ट के कारण बिजनेस में नुकसान उठाने वाली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी मदद मिल सकती है। MSME को डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सुरक्षा के उपायों जैसे ट्रेड से जुड़े उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट जल्द ही वकीलों का एक पैनल बना सकता है। इसके बारे में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, 'इसमें सस्ते इंपोर्ट के कारण ट्रेड में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ याचिका दायर करने करने में मदद दी जा सकती है।' आमतौर पर, MSME के लिए इन मामलों में वकीलों की फीस देना और प्रक्रिया को समझना आसान नहीं होता। बहुत से देशों ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ट्रेड को संरक्षण देने वाले उपाय किए हैं। इससे भी मुश्किलें बढ़ी हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सस्ते आयात से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और कुछ अन्य उपाय शामिल हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान देश का ट्रेड डेफिसिट 106.84 अरब डॉलर था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने बताया, 'एक बड़ी समस्या यह है कि MSME को यह समझने में देर लगती है कि प्रॉडक्ट की डंपिंग या इंपोर्ट बढ़ गया है और वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि इस तरह के मामलों में राहत की प्रक्रिया पर अधिक खर्च होता है जो छोटी फर्में नहीं उठा सकती।' डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) ने पहले ही गलत कारोबारी तरीकों से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। एंटी-डंपिंग जांच में 2019 में औसत 32 दिन लगे थे। यह अवधि 2017 में 119 दिन और 2016 में 259 दिन की थी। DGTR ने गलत कारोबारी तरीकों पर लगाम लगाने के लिए उपलब्ध उपायों के अधिक इस्तेमाल के उद्देश्य से एक हेल्प डेस्क भी बनाया है।

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
OUR STRENGTH • हमारी शक्ति
सत्यमेव जयते
Ministry of MSME, Govt. of India

सऊदी अरामको ने ग्रीन शू विकल्प का इस्तेमाल किया, IPO रेकॉर्ड 29.4 अरब डॉलर पर

दुबई। एजेंसी

सऊदी अरब की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरामको का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) रेकॉर्ड 29.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह पूर्व में घोषित आंकड़े से अधिक है। कंपनी ने 'ग्रीन शू विकल्प' का इस्तेमाल कर निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए लाखों और शेयर बेचे हैं, जिससे आईपीओ की राशि बढ़ गई है।

45 करोड़ अतिरिक्त शेयरों की बिक्री

कंपनी ने कहा कि आईपीओ प्रक्रिया के तहत 45 करोड़ अतिरिक्त शेयरों की बिक्री की गई। इस कंपनी की बहुलांश हिस्सेदारी सरकार के पास है। कंपनी ने 11 दिसंबर को स्थानीय सऊदी तदावुल एक्सचेंज में कारोबार शुरू किया था।

दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी

कारोबार के दूसरे दिन कंपनी का शेयर 10 डॉलर प्रति शेयर पर पहुंच गया था, इससे अरामको का बाजार पूंजीकरण 2,000 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे वह बड़ी आसानी से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई।

कंपनी ने 1.7% अतिरिक्त शेयर बेचे

अतिरिक्त शेयरों की बिक्री का मतलब है कि अरामको ने सार्वजनिक रूप से अपने 1.7 प्रतिशत शेयर बेचे हैं। अतिरिक्त शेयरों की बिक्री से पहले ही अरामको का आईपीओ दुनिया की सबसे बड़ी शेयर बिक्री बन चुका था।

जनवरी में 8% से ऊपर जा सकती है महंगाई दर, RBI के लिए चुनौती : एसबीआई रिपोर्ट

नई दिल्ली। प्याज और आलू जैसी सब्जियां महंगी होने से दिसंबर में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर बढ़कर 2.59 प्रतिशत पर पहुंच गई। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर पांच सालों के उच्चतम स्तर 7.35 फीसदी पर पहुंच चुकी है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा महंगाई दर जनवरी महीने में आठ फीसदी को पार कर सकती है। उसके बाद इसमें गिरावट आएगी।

मार्च तक महंगाई दर 7 फीसदी के ऊपर

इतनी ज्यादा महंगाई के बीच रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत दरों में कटौती करना संभव नहीं लग रहा है। दिसंबर बैठक में भी रिजर्व बैंक ने दरों में बदलाव नहीं किया था। अगली बैठक फरवरी के पहले सप्ताह में होगी। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक, इस परिस्थिति में लग नहीं रहा है कि रिजर्व बैंक रेट में कटौती का फैसला लेगा। महंगाई को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च तक खुदरा मुद्रास्फीति सात प्रतिशत से ऊपर बनी रह सकती है।

दिसंबर में प्याज की कीमत 455.83 प्रतिशत बढ़ी

दिसंबर में खाद्य वस्तुओं के दाम 13.12 प्रतिशत बढ़े। एक महीने पहले यानी नवंबर में इनमें 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इसी तरह गैर खाद्य उत्पादों के दाम चार गुना होकर 7.72 प्रतिशत पर पहुंच गए। नवंबर में गैर खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 1.93 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं में माह के दौरान सब्जियां सबसे अधिक 69.69 प्रतिशत महंगी हुईं। इसकी मुख्य वजह प्याज है जिसकी मुद्रास्फीति माह के दौरान 455.83 प्रतिशत बढ़ी।

आलू के दाम 44.97 प्रतिशत चढ़ गए

इस दौरान आलू के दाम 44.97 प्रतिशत चढ़ गए। प्रमुख उत्पादक राज्यों में भारी बारिश से फसल बर्बाद होने की वजह से हाल तक विभिन्न बाजारों में प्याज 100 रुपये प्रति किलो से अधिक के भाव पर बिक रहा था। नई फसल की आवक और आयात के बाद अब प्याज कीमतें नीचे आ रही हैं। इससे पहले सोमवार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 7.35 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो इसका पांच साल का उच्चस्तर है।

आयुष्मान भारत योजनाः एनएचए ने आईटीसी ई-चौपाल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली। केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन करने वाली प्रमुख एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने आईटीसी ई-चौपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि किसानों को इस कार्यक्रम के तहत लाभ दिलाने में मदद की जा सके। इस एमओयू पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए गए और इसके तहत आईटीसी 400 ग्राम स्वास्थ्य चैंपियन (वीएचसी) के जरिए प्रायोगिक आधार पर जागरूकता शिविर आयोजित करेगी। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 800 से अधिक गांवों को शामिल किया जाएगा। ये वीएचसी समूह बैठकों और घर-घर अभियानों के माध्यम से महिलाओं और किशोरों को कार्यक्रम के बारे में जागरूक करेंगे। आईटीसी ई-चौपाल मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों के 35,000 से अधिक गांवों में करीब 40 लाख किसानों का नेटवर्क है। एनएचए के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ प्रवीण गेदाम और आईटीसी में कॉर्पोरेट मामलों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल के राजपूत ने हस्ताक्षर किए। एनएचए द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी।

खाद्य तेल उद्योग निकाय ने रिफाइंड पामतेल के आयात की सीमा तय लागू करने की मांग की

नयी दिल्ली। एजेंसी

स्थानीय तेलशोधन करने वाली कंपनियों और तिलहन उत्पादकों को संरक्षित करने के लिए सरकार को प्रति माह 50,000 टन रिफाइंड पामतेल और पामोलिन का आयात करने की सीमा तय करनी चाहिए।खाद्यतेल प्रसंस्करण उद्योग के मंच एसईए ने मंगलवार को यह सुझाव रखा। भारतीय सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स संघ (एसईए) ने सरकार से पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने को कहा है। एसईए ने इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को एक ज्ञापन दिया है। पिछले हफ्ते, सरकार ने एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश मलेशिया द्वारा नए नागरिकता कानून और कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी करने की वजह से रिफाइंड पाम तेल और पामोलिन के आयात पर कुछ रोक लगाया था। एसईए के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने वाणिज्य मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मीडिया की खबरों से लगता है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य की एजेंसियों और निजी संगठनों को रिफाइंड पाम तेल के आयात के लिए लाइसेंस जारी कर सकती है। चतुर्वेदी ने कहा, ''हमें आशंका है कि अगर इस मामले में उपयुक्त सीमा नहीं तय की गयी तो भारत में रिफाइंड पाम तेल और पामोलिन की भरमार हो सकती है।'' एसईए ने इन तेलों के आयात पर मासिक 50,000 टन की सीमा रखने का सुझाव दिया है। भारत सालाना लगभग 1.5 करोड़ टन वनस्पति तेलों का आयात करता है। इसमें पाम तेल का हिस्सा 90 लाख टन है। बाकी 60 लाख टन सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का आयात होता है। पामतेल मुख्यतः इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है।

शिनाख्त तकनीकी के लिए भारत संबंधी खास डाटा की जरूरत

बेंगलुरु। भारत में सार्वजनिक जगहों पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने की डिजिटल प्रणालियां इस वर्ष से लागू करने की योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ एवं इंफोसिस के सह - संस्थापक कृष गोपालकृष्णन ने विशेष रूप से देसी विशेषताओं वाला डाटा जमाकरने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस नई प्रौद्योगिकी को प्रभावी तरह से लागू करने के लिए अपने यहां की विशेषताओं से जुड़ा डेटाबेस विकसित करने की जरूरत है। जिसमें कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग शामिल हो। फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जो किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट और आकार के आधार पर विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। गोपालकृष्णन ने कहा कि भारत को चेहरे से पहचान प्रणाली को लागू करने से पहले खुद परीक्षण करना चाहिए क्योंकि वर्तमान में इन प्रौद्योगिकियों को तैयार करने में उपयोग होने वाले आंकड़ों में भारत के आंकड़े कम हैं और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रौद्योगिकी देश में ठीक से काम करेगी या नहीं। इंफोसिस के पुरस्कार समारोह से इतर गोपालकृष्णन ने समाचार एजेंसी से कहा , ' हमें पूर्वाग्रहों पर भी विचार करना होगा। मेरा मानना है कि भारत को कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग में शोध करना चाहिए क्योंकि प्रणालियों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अधिकांश डेटाबेस , जिन्हें आज उपयोग किया जा रहा है , उसमें भारत के आंकड़े शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग नए उत्पादों और नई सेवाओं को बनाने के लिए आंकड़ों (डेटा) का लाभ उठाने में किया जा सकता है। इसमें चेहरे से पहचान , अनुवाद और डायग्नोस्टिक्स शामिल हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने पिछले साल कहा था कि चेहरे से पहचान प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है। इससे अपराधियों को पकड़ने और गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद मिलेगी। तकनीकी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के इस तकनीक को निजता के लिए खतरा बताने को लेकर पूछने पर गोपालकृष्णन ने कहा , ' हमें चेहरे की पहचान तकनीक को नियंत्रित करने वाली नीति बनानी चाहिए क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है।' उन्होंने कहा , 'हमें अपना डेटाबेस बनाने की जरूरत है। डेटाबेस में भारत से पर्याप्त आंकड़े शामिल होना चाहिए। '

त्याग, वैराग्य, कर्म व सत्य की क्रांति का पर्व

मकर संक्रांति से सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में प्रखर होने लगती हैं। सूर्य देव की गति तेज हो जाती है। मनुष्यों में भी नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। मकर संक्रांति का पर्व त्याग और तप का भी संदेश देता है। यह क्रांति यानी परिवर्तन का संदेश देता है

मकर संक्रांति (15 जनवरी) पर विशेष

आनन्दमूर्ति गुरुमां

जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति होती है। इस दिन से अगले छह महीने के लिए उत्तरायण पक्ष शुरू हो जाता है। इसको देवताओं का काल भी कहते हैं। इससे पहले के छह महीने, जिसे हम दक्षिणायण पक्ष कहते हैं, उसमें देवता सोए हुए होते हैं। इसलिए राक्षसों की तमोगुणी वृत्तियों का वर्चस्व होता है।

मकर संक्रांति को पंजाबी में संक्रांत बोलते हैं और हिंदी में संक्रांति बोलते हैं। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि, शनि की राशि मानी जाती है। आमतौर पर लोग बोलते हैं कि शनि बुरा होता है, पर सच यह है शनि तप देते हैं। कोई भी तपस्वी हो, महात्मा हो, उसके ग्रह-नक्षत्रों की सूची में शनि की स्थिति बहुत अच्छी होती है। शनि के प्रभाव से वह व्यक्ति बहुत कठोर तप कर सकता है।

शनि वैराग्य का चिह्न हैं, इन्हें शिव जी का अंश भी बोलते हैं। शनि सूर्य-पुत्र भी हैं, शिवांश भी हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य जैसा तेज, तप और उज्ज्वलता जीवन में आ सकती है, शिव जी जैसा तप, वैराग्य, योग जीवन में आ सकता है।

जो चीज संसार के लिए बुरी है, वह अध्यात्म के लिए बहुत अच्छी होती है। वैराग्य आना तो अच्छी बात है। जीवन में तप आए, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है! अभी आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस्य है। आलस्य होता है, तभी पौष महीने की सर्दी में सुबह उठना मुश्किल लगता है। ऐसा व्यक्ति तप कैसे करेगा? तप करने के लिए तो मोटे कपड़ों की परत से बाहर आना पड़ेगा। जो लोग ज्योतिष नहीं समझते हैं, वे अजीब-अजीब धारणाएं बना लेते है। लेकिन सच यह है कि शनि तप देते हैं, शनि वैराग्य देते हैं। शनि ज्ञान के देवता हैं। शनि मतलब कि आपके मन में त्याग के, वैराग्य के, ज्ञान के, सेवा के विचार उठने लग जाते हैं।

ऐसे तो संक्रांति हर महीने आती है, पर सूर्य का मकर राशि में आना, यह मकर संक्रांति है। यह विशेष हो जाती है। इस दिन लोग दान करते हैं- तिल का दान, गुड़ का दान, गाय को चारा देना वगैरह। पवित्र नदियों में स्नान करते हैं- गंगा-स्नान, त्रिवेणी स्नान। असली स्नान तो ज्ञान का है। जो ज्ञान का स्नान न कर सके, वही गंगा में स्नान करने जाएगा। जिसने अपने मन के अंदर ही गंगा को जाग्रत कर लिया है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। संत रैदास जी का कथन है, 'जो मन चंगा तो कठौती में गंगा।' मन चंगा हो, तो इसी मन के बर्तन में गंगा जी प्रगट हो जाएंगी।

अध्यात्म मार्ग में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। संक्रांति से पहले लोहड़ी होती है, जिसमें रात्रि को अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लोहड़ी वास्तव में एक यज्ञ है, जिसकी अग्नि में साधक अपनी सब कमियों, कमजोरियों और आलस्य को जला देता है और मकर संक्रांति से एक नई शुरुआत करता है। संक्रांति माने क्रांति। संक्रांति से मतलब है- सत्य के संग क्रांति, संत के संग क्रांति। जिसके जीवन में संत नहीं है, उसके जीवन में कभी क्रांति नहीं होती। उनके जीवन में सिर्फ अशांति होती है, क्योंकि वस्तुओं से ही मोह होता है। कोई वस्तु मिल गई तो खुश हो जाएगा, नहीं मिली तो रोता रहेगा। व्यक्तियों से मोह होगा, कोई प्यार करेगा तो बड़ा खुश होगा और प्यार नहीं करेगा तो बैठकर रोएगा कि हाय! मुझे कोई प्यार नहीं करता। वस्तुओं के और व्यक्तियों के पीछे भागता है, तो दुख पाता है और संत के संग रहता है, तो वह यह जानता है कि मुझे बाहर कुछ ढूंढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मेरा आनंद तो मुझ ही में है, क्योंकि मैं अस्ति-भाति-प्रिय स्वरूप हूं। ये देह मैं हूं नहीं, तो देह का जन्म मेरा नहीं, देह का मरण मेरा नहीं, देह का रोग मेरा नहीं, देह की अशुद्धि मेरी नहीं। मैं मन नहीं, तो मन के पाप-पुण्य मैं नहीं, मेरे नहीं। मन की कमी, कमजोरी मैं नहीं, मेरी नहीं। मन के अशुद्ध विचार मैं नहीं,

> संक्रांति का अर्थ है क्रांति। इससे तात्पर्य है- सत्य के संग क्रांति, संत के संग क्रांति। जिसके जीवन में संत नहीं है, उनका संग नहीं है, उसके जीवन में कभी क्रांति नहीं होती।

मेरे नहीं। मैं तो नित्यमुक्त, सच्चिदानंद, अनादि अनंत, निर्वचनीय विलक्षण स्वरूप हूं, आत्मतत्व के निश्चय में रहता हूं। बाहर संसार में जो दिखता है, वो दिखती हुई हर वस्तु मिथ्या है, बदलने वाली है। जो बदलने वाला है, उसके साथ मैं अपना मन क्यों जोड़ूं? मेरा मन किसका मनन करेगा? मेरा मन आत्मतत्व का मनन करेगा।

साधक के लिए कहा गया कि मकर संक्रांति के दिन वह गुरु का दर्शन करे, दान करे, जप करे, स्नान करे। मैं तो कहती हूं कि अपने पूरे जीवन को प्रसन्नता से भरो, मुस्कुराहटों से भरो। निराशा से नहीं भरो, आशा से भी नहीं भरो, प्रभु की स्मृति से भरो, भक्ति से भरो, प्रेम से भरो, सेवा से भरो, जप से भरो। इनके साथ अपने जीवन को अच्छा रंग दो। संक्रांति को अपने मन में तप का रंग भरो।

सबके कल्याण का पर्व मकर संक्रांति

मकर संक्रांति का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। इस दिन स्नान, दान और जप का बहुत महत्व है। इस दिन किस प्रकार सूर्य उपासना करें, किस वस्तु का दान करें, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉ. दत्तात्रेय होस्केरे

मंगलवार रात्रि 2.06 बजे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य उत्तरायण के हो जाएंगे, अर्थात सूर्य पृथ्वी के उत्तरी भाग में अपना अधिकाधिक प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। सूर्य का यह संक्रमण शुक्र प्रधान पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और शोभन योग में हो रहा है, जो सभी के लिए अत्यंत लाभप्रद है।

एक कथा के अनुसार, शनि देव को उनके पिता सूर्य देव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्य देव ने शनि देव और उनकी मां छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनि और उनकी मां ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्य देव ने क्रोध में आकर शनि देव और उनकी माता के घर 'कुंभ', जो शनि प्रधान राशि है, को जला दिया। इससे माता छाया और पुत्र शनि दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देख उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मान सूर्य देव शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। कुंभ में आग लगने के बाद वहां काले तिल के अलावा सब कुछ जल गया था। इसीलिए शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव की पूजा काले तिल से की। इसके बाद सूर्य देव ने शनि को उनका दूसरा घर 'मकर' दिया। मान्यता है कि शनि देव को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई, तभी से मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है।

चंद्र के शुक्र प्रधान पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए सूर्य का राशि परिवर्तन सभी के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि यह संयोग सभी की एकरूपता को भंग करेगा, जिससे नए विचार और नए दृष्टिकोण विकसित होंगे। नए अवसर भी प्राप्त होंगे। वे लोग, जो प्रगति नही कर पा रहे, उन्हें प्रगति की नई इच्छाशक्ति प्राप्त होगी। धन-धान्य की परिपूर्ति भी होगी।

संक्रांति की तिथि बदलना, खगोलीय घटना है। कुल बारह राशियां है और माह भी बारह हैं। सूर्य प्रत्येक माह अपनी राशि बदलता है। प्रत्येक राशि में 30 अंश (डिग्री) होते हैं। इस तरह से सूर्य का एक दिन 1 अंश के बराबर होता है और इसीलिए वह 30 अंश पूरे होते ही राशि बदलते हैं। पृथ्वी सौरमंडल में अपने अक्ष पर तो घूमती

ही है, साथ ही अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने स्थान में भी परिवर्तन करती रहती है। पृथ्वी के इस व्यवहार के कारण लगभग प्रत्येक 27,500 वर्ष के बाद पृथ्वी के स्थान में व्यापक परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए सौर स्थिति पर आधारित इस पर्व की तिथि में भी परिवर्तन आता है।

सूर्य संबंधी दोषों से होंगे आप मुक्त

सूर्य संबंधी दोषों के समाधान के लिए यह संक्रांति अत्यंत कारक समय होगा। यदि आप रक्त, संतान, मस्तिष्क संबंधी समस्या या उच्च रक्तचाप से परेशान हैं, तो यह लक्षण है कि आप की कुंडली में सूर्य या तो नीच का होकर तुला राशि में स्थित हैं या वृषभ, धनु या मीन राशि में है।

उपायः स्वास्थ्य संबंधी इन समस्याओं के समाधान हेतु बुधवार 15 तारीख को प्रातःकाल एक ताम्बे के पात्र में जल लेकर उस में कुंकुम, शक्कर और एक बेलपत्र डालें और इस मंत्र से सूर्य को सात बार जल दें- 'नमो नमः सहस्त्रांशु आदित्याया नमो नमः ह्रीं सूर्याय नमः'। तिल, लाल वस्त्र, हरे फल और शक्कर या गुड़ का दान करें। हर रविवार को सूर्य को इसी तरह जल दें।

आप रोजगार की स्थिति से परेशान हैं और आर्थिक समस्या, ऋण संबंधी समस्या से भी ग्रस्त हैं, तो रविवार को यह उपाय करें- लाल आसन पर बैठ कर इस मंत्र का जाप करें। 'ह्रीं श्रीं आदित्य वर्णे तपसोधि जातों ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः॥' तत्पश्चात शिवालय में जाकर शिव मंत्रों का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। सायंकाल लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर एक नारियल पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अर्पित करें। लाभ होगा।

मंत्र जाप व दान का पर्व आपको लाभ देगाः

राशियों के अनुसार सफेद तिल के साथ निम्न मंत्रों का जाप करने के बाद निर्दिष्ट सामग्रियों का दान किया जाए, तो ग्रह दशा अनुकूल होगी।

मेषः मंत्र- ऊं रवये नमः।
दान सामग्री- गुड़।
वृषभः मंत्र- ऊं मित्राय नमः।
दान सामग्री - शक्कर।
मिथुनः मंत्र- ऊं खगाय नमः।
दान सामग्री-सिंघाड़ा, नारियल।
कर्कः मंत्र- जय भद्राय नमः।
दान सामग्री- दूध और चावल।
सिंहः मंत्र- ऊं भास्कराय नमः।
दान सामग्री-अनार।
कन्या : मंत्र- ऊं भानवे नमः।
दान सामग्री- हरे फल।
तुलाः मंत्र- ऊं पुष्णे नमः।
दान सामग्री- चावल, खट्टे फल।
वृश्चिकः मंत्र- ऊं सूर्याय नमः।
दान सामग्री-दूध और गुड़।
धनुः मंत्र- ऊं आदित्याय नमः।
दान सामग्री- चना दाल, गुड़।
मकरः मंत्र- ऊं मरीचये नमः।
दान सामग्री - मूंगफली।
कुम्भः मंत्र- ऊं सवित्रे नमः।
दान सामग्री- शक्कर, उड़द दाल।
मीनः मंत्र- ऊं अर्काय नमः।
दान सामग्री - बेसन की मिठाई।

आपकी जेब के लिए क्या बुरा होने वाला है साल 2020

नई दिल्ली। एजेंसी

प्याज और टमाटर समेत कई सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 7.35 पर्सेंट दर्ज की गई, जो अनुमान से कहीं ज्यादा है। ऐसे में आर्थिक गलियारों में चिंताएं बढ़ गई हैं। हर किसी के मन में यही सवाल हैं कि आगे की राह कैसी होगी? आइए कुछ तथ्यों को देखते हुए समझते हैं कि क्या आपकी जेब के लिए यह साल कैसा रह सकता है।

बढ़ती कीमतें?

सोमवार को महंगाई के आंकड़े सामने आए। दिसंबर के महीने में महंगाई दर बढ़कर 7.35 पर्सेंट पर पहुंच गई। अकेले फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो एक महीने पहले यानी नवंबर में जो 10.01 पर्सेंट था, वह दिसंबर में बढ़कर 14.12 पर्सेंट हो गया। इस दौरान सब्जियों के दामों में 60.5% तक का इजाफा हुआ है। एक महीने पीछे जाएं तो नवंबर 2019 में खुदरा महंगाई दर 5.54% थी। हालांकि अक्टूबर के मुकाबले यह भी ऊंचे लेवल पर थी। अक्टूबर में इन्फ्लेशन 4.62% था। मार्च के महीने से फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण प्याज की बढ़ती कीमतें रहीं।

महंगे कर्ज?

जुलाई 2016 के बाद पहली बार महंगाई दर ने RBI के 2-6% के टारगेट बैंड को तोड़ा है। कीमत स्थिरता केंद्रीय बैंक की मुख्य प्राथमिकता है। पिछले महीने पेश की गई मौद्रिक समीक्षा में RBI ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था, जो अप्रत्याशित था क्योंकि लगातार 5 बार केंद्रीय बैंक कटौती कर चुका था। 5 बार में आरबीआई ने रीपो रेट में 1.35% की कटौती की, लेकिन छठी बार रेट नहीं बदले। महंगाई दर स्थायी है या अस्थायी, यह तय करने को लेकर आरबीआई सिर्फ कुल महंगाई दर को नहीं देखता बल्कि कोर इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखता है। कोर इन्फ्लेशन 3.7 पर्सेंट रहा, जो 4% के नीचे बना हुआ है। साथ ही, फिलहाल महंगाई बढ़ने के पीछे सब्जियों के बढ़ते दाम मुख्य कारण हैं, जो मार्च में गिरने लगेंगे क्योंकि उस समय तक सप्लाई जोर पकड़ लेगी। लिहाजा, संभव है कि 6 फरवरी को होने वाली अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में दिसंबर की महंगाई के आधार पर नीतिगत दरों में कटौती न हो।

रोजगार?

आर्थिक सुस्ती के कारण मौजूदा वित्त वर्ष में 16 लाख कम मौकरियों के सृजन का अनुमान है। बीते वित्त वर्ष में 90 लाख नई नौकरियां पैदा हुई थीं, लिकिन इस साल यह आंकड़ा काफी कम रह सकता है। यह बात एसबीआई की रीसर्च रिपोर्ट में सामने आई है। ईंइध द्वारा नए पेरोल्स का हवाला देते हुए यह आंकड़ा पेश किया गया है। ईंइध के डेटा में सरकारी सरकारी, राज्य सरकारों के तहत आने वाली नौकरियां और प्राइवेट जॉब्स का डेटा नहीं शामिल होता क्योंकि साल 2004 से यह डेटा नैशनल पेंशन स्कीम के तहत आने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'दिलचस्प है कि 2019-20 में NPS कैटिगरी में भी केंद्र और राज्य सरकारें 39000 कम रोजगार पैदा करेंगी।' पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रॉडक्टिविटी ग्रोथ तकरीबन समान रही, जिसकी वजह से सैलरी ग्रोथ भई कम रही। मार्केट में कम जॉब्स का मतलब है कि इन्किमेंट भी कम होगा।

क्या है रास्ता?

ऐसा समय जब इकॉनमी में खपत और निवेश के लिए मांग घट रही है, बढ़ती महंगाई ने RBI के सामने और संकट खड़े कर दिए हैं। नीतिगत दरों में बदलाव के लिए काफी कम गुंजाइश बचती है। सभी की नजरें अब 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर हैं। जनता देखना चाहती है कि 10 सालों में पहली बार 5% की दर से बढ़ रही इकॉनमी की ग्रोथ बूस्ट करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है।

मर्सिडीज-बेंज भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतरी, ईक्यू ब्रांड को किया पेश

पुणे। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने मंगलवार को ईक्यू ब्रांड पेश करने के साथ भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कदम रखने की घोषणा की। कंपनी की अप्रैल में अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन 'ईक्यूसी' पेश करने की योजना है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने कहा कि ईक्यू ब्रांड की पेशकश देश में लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में कंपनी की रणनीतिक पहल को दर्शाती है।

कोकिंग कोयले के आयात को मंगोलिया, रूस से बात कर रहा है भारतः प्रधान

कोलकाता। भारत कोकिंग कोयले के आयात के लिए मंगोलिया तथा रूस से बातचीत कर रहा है। इससे देश की कोकिंग कोयले के आयात को कुछ देशों पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। केंद्रीय इस्पात तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि हम कोकिंग कोयले के आयात पर विचार कर रहा है। यह इस्पात विनिर्माण में काम आने वाला एक प्रमुख कच्चा माल है। प्रधान ने कहा कि हम उचित मूल्य पर कोकिंग कोयले का आयात करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत 2030-31 तक इस्पात उत्पादन को 30 करोड़ टन पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रधान ने शनिवार शाम को यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "भारत द्वारा आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया जा रहा है, जो अच्छा है। लेकिन मंगोलिया में भी अच्छी गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध है। हमारी इस बारे में मंगोलिया सरकार से बातचीत चल रही है। वर्ष 2016 में इस्पात मंत्रालय और सेल के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कोकिंग कोयले के आयात का करार करने मंगोलिया की राजधानी उलनबटोर में गया था। शुरुआती योजना इसका आयात चीन के बंदरगाह के जरिये करने की थी, लेकिन यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब सरकार रूस के वोस्तोस्चनी बंदरगाह के जरिये कोकिंग कोयला लाने का प्रयास कर रही है। प्रधान ने कहा कि हमने भारत सरकार की ओर से रूसी अधिकारियों के साथ भी बातचीत शुरू की है।

एफ़सीए इंडिया ने BS- VI डीजल ऑटोमैटिक वैरिएंट्स लॉन्च कर जीप कम्पास रेंज का विस्तार किया

सभी 80 एफसीए डीलर शोरूम्स में बुकिंग शुरू, टेस्ट ड्राइव का भी अनुभव कीजिए

मुंबई। एफसीए इंडिया ने आज 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ दो टर्बो-डीजल वैरिएंट्स पेश करके जीप कम्पास रेंज का विस्तार करने की घोषणा की। ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी / 4x4) कॉन्फ़िगुरेशन में ग्राहकों को दो वैरिएंट्स - लॉन्गिट्यूड और लिमिटेड प्लस - की पेशकश की जाएगी और यह स्थानीय रूप से निर्मित BSVI –कॉम्प्लाएंट 2.0-लीटर 173 एचपी, 350 एनएम टर्बो-डीजल इंजन द्वारा पावर्ड होगी।

जीप कम्पास 4x4 लॉन्गिट्यूड 9एटी ग्राहकों को 21.96 लाख रुपए में और लिमिटेड प्लस 24.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम, अखिल-भारत) में उपलब्ध होगी। 68 भारतीय शहरों में मौजूद एफसीए की सभी 80 अधिकृत डीलर शोरूम में बुकिंग खुल चुकी हैं और टेस्ट ड्राइव भी दी जा रही है।

श्रृंखला के विस्तार पर टिप्पणी करते हुए, डॉ. पार्थ दत्ता – प्रेसिडेंट और मैनजिंग डायरेक्टर, एफसीए इंडिया ने कहा, 'हम चार डीजल ऑटोमैटिक वैरिएंट की पेशकश के साथ जीप कम्पास रेंज को मजबूत और विस्तारित कर रहे हैं, जिनमें से, बेस और टॉप-एंड वैरिएंट अभी से उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। दोनों वैरिएंट्स में अधिक इक्विपमेंट हैं, जोकि ग्राहक के लिए पैसे के महत्व को बढ़ाते हैं और हमारा मानना है कि यह सेगमेंट में हमारी हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। इस रोल आउट ने हमें वैधानिक समयसीमा से बहुत पहले उपभोक्ताओं को हमारे स्थानीय स्तर पर निर्मित BSVI-कॉम्प्लाएंट 2.0-लीटर टर्बो-डीजल पावरट्रेन की पेशकश करने का अवसर दिया है।'

जीप कम्पास डीज़ल ऑटोमैटिक रणनीति

जीप कम्पास 9-स्पीड ऑटोमैटिक रेंज का रोल आउट इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रमाणित 2.0 लीटर 173 एचपी 350 एनएम टर्बो-डीज़ल पावरट्रेन का

BSVI- कॉम्प्लाएंट वर्जन अब मुख्यधारा का उत्पादन है। रंजनगांव में एफसीए के जेवी विनिर्माण सुविधा में इस पावरट्रेन का स्थानीय रूप से उत्पादन किया गया है।

जीप डीजल ऑटोमैटिक रेंज इक्विपमेंट के स्तर को कुछ हद तक बढ़ाती है, खासकर मिड रेंज वैरिएंट, लॉन्गिट्यूड में। जीप कम्पास के ग्राहकों का बड़ा हिस्सा रेंज के उच्च एंड की ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए लॉन्गीट्यूड में फिलहाल इस वैरिएंट द्वारा पेश किये जाने वाले उपकरणों की तुलना में अधिक उपकरण को जोड़ना रुचिकर ग्राहकों और अधिक लुभाएगा। लॉन्गिट्यूड और लिमिटेड प्लस के बीच प्राइसिंग और इक्विपमेंट में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी वैरिएंट में रुचिकर ग्राहकों के साथ न्याय किया जा सके।

लॉन्गिट्यूड पैकेज अब अधिक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल (पहली बार इस ट्रिम में पेश किया गया है), रिवर्स कैमरा और डायनेमिक ग्रिड लाइनों की कार्यक्षमता के साथ बड़ा 7-इंच यूकनेक्ट स्क्रीन, डुअल-जोन एयर कंडीशनिंग और टू-टोन इंटीरियर्स, वाहन के लिए पैसिव एंट्री और पुश बटन स्टार्ट के साथ पेश किया गया है। कम्पास पोर्टफोलियो में सभी वैरिएंट की तरह, लॉन्गिट्यूड में पहले से ही स्टैंडर्ड फीचर्स जैसे ऑल-सीजन टायर्स के साथ 17-इंच एलॉय शॉड, सेफ्टी ऐड्स जैसे एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल (टीसी) और हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), सभी चार पहियों पर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) और फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड सस्पेंशन (एफएसडी) मौजूद हैं। यह जीप 4x4 डीएनए को सेलेक्टेरेन एडब्लूडी सिस्टम में ले जाता है जो 4 मोड्स - ऑटो, सैंड, मड और स्नो से लैस है। लिमिटेड प्लस जीप कम्पास पोर्टफोलियो में नॉन-ट्रेल रेटेड वैरिएंट्स के बीच में सबसे बेहतरीन है और बेस और मिड वैरिएंट में पेश किए जाने वाले सभी उपकरणों और फीचर्स के साथ-साथ अतिरिक्त खूबियों के साथ आता है, जिस कारण यह लाइन-अप की सबसे प्रीमियम पेशकश है।

लिमिटेड प्लस में अन्य प्रमुख और लोकप्रिय विशेषताएं हैं - 8.4 इंच की बड़ी यूकनेक्ट इंफ़ोटेनमेंट स्क्रीन, डुअल-पैन पैनोरमिक सन/मून रूफ, आलीशान लेदर के इंटीरियर्स, ड्राइवर के लिए 8-वे पावर्ड सीट, ऑटो हेडलैंप, रेन सेंसिटिव वाइपर्स, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, 6 एयरबैग्स और 18 इंच के अलॉय व्हील्स सहित कई अन्य स्टैंडर्ड फ़ीचर्स भी हैं। डॉ. दत्ता ने अंत में कहा, 'हम अपने ग्राहकों को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक लाइफ़स्टाइल प्रदान करते हैं। जहां जीप कम्पास हर आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से सुसज्जित है, जिसकी उम्मीद आजकल ग्राहक हर वाहन में करते हैं, हमने हमेशा ठोस इंजीनियरिंग, समझौता न की जाने वाली सुरक्षा और बेजोड़ 4x4 क्षमता के अपने मूल सिद्धांतों को बनाए रखा है, ये सभी 80 साल की मजबूत जीप वंशावली के लिए सच हैं।'

Polymer MIS

Market Intelligence Source

In this information age having latest news, information, data and analysis is critical to the success of any business. We at PolymerMIS provide you exactly with this for Polymer and Petrochemical Industries, to help you have an edge over your competitors and stay ahead of them in every segment.

We bring to you on real time basis with breaking news as it happens, including market trends, quotes, moves, analysis, data, predictions and much more. We provide everything you need to know to stay informed and react to changing market conditions.

Advantages of Being with PolymerMIS

• Most important, its Economical. • Information on fingertips - SMS based alerts. • Quickest method of information delivery. • No hassle to browse to reach the content applicable for you. Pay for only what you need. • Covers Wide range of petrochemical products and feedstock including Aromatics, Olefins, crude oil, Polymers etc.

Sample SMS from PolymerMIS

Brent Crude Oil $48.83 US$/Rs.65.66 Propylene $605 CFR China Ethylene $1000 CFR NEA Naphtha $460 CFR Japan Styrene $920 CFR China.

PE market Updates - Intl. market assessed as firm amid short supply and higher Ethylene of 1005$ in SE Asia. November offers for India are above 1200$ for LL/HD/LD. Converters are keeping low inventories due to upcoming festivals and we may see revival of demand after 15th November.

RIL reduced PP Prices by Rs. 2000/MT and PP Random by Rs. 3000/MT Price Protection withdrawn w.e.f. 1 November 2015.

Various Plans we offer

We provide two broad categories of Plans for subscription:-

SMS Plan - In SMS Plan, we provide you SMS based alerts on Market Prices for Various Polymers and Daily Updates on Plants, Crude, Forex, Market Trend and Projections, Market Moves, Corporate Actions, Impact of Global changes etc.

Web Plan - PolymerMIS has emerged one of the Best Web Plan among thousands of our clients in India and across the world. Where our clients will get sms alerts and web access on our portal for Domestic and International Plastic Industry updates, Breaking News, Instant News alerts, Trend Analysis, Technical Analysis, Historic Data, Comparison of various Grades as well as Daily Newsletter, Latest News and Updates of HDPE, LDPE, LLDPE, PP, EVA, PVC, GPPS, HIPS, ABS, SAN and all Feedstock Prices and Market Trends on relevant subjects without cluttering your inbox. We bring whole Polymer industry under your thumb by providing our complimentary Android and ios Services. We want all our customers to have a fantastic experience with our latest news and updates. Our goal is to inform you before anyone else. We always effort to present you the best possible services every time. There's more to know about Polymer industry. Kindly visit at www.polymermis.com

VISTA WEBSOFT PRIVATE LIMITED

Corporate Office:
402 Morya Blue Moon,
B-57 off New Link Road,
Fortune Terrace Lane,
Andheri West, Mumbai -400053, India
Tel.: +91-22-26736570, Fax: +91-22-26736522,
Email: sales@polymermis.com

Branch Office :
2/12, South Tukoganj,
Near Noble Hospital,
Indore, M.P. 452001, India
Tel: +91-731-4068185, Fax: +91-731-4068185,
Email: sales@polymermis.com

Visit us at : www.polymermis.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।